

भारत सरकार  
नागर विमानन मंत्रालय  
लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : 3568

दिनांक 24 मार्च, 2022/ 3 चैत्र, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

देश में हवाई पट्टियों का उन्नयन

3568. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

श्री कुलदीप राय शर्मा:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) देश में निष्क्रिय का कभी-कभार ही प्रचालनरत हवाई पट्टियों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) देश में गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त निष्क्रिय या कभी-कभार प्रचालनरत हवाई पट्टियों के रखरखाव पर हुए राजस्व और व्यय का हवाई पट्टी-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) देश में बड़ी संख्या में हवाई पट्टियों के अप्रयुक्त पड़े रहने के क्या कारण हैं;
- (घ) क्या सरकार का इन हवाई पट्टियों को पुनः प्रचालित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (ङ.) सरकार द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में प्रमुख हवाई पट्टियों के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.), विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

- (क): भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के गैर-परिचालित हवाईअड्डों की सूची अनुबंध- I के रूप में संलग्न है।
- (ख): भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के गैर-परिचालित हवाईअड्डों के संबंध में पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए राजस्व और व्यय का हवाईअड्डा-वार विवरण, अनुबंध-II के रूप में संलग्न है।
- (ग)से (ङ.): नागर विमानन मंत्रालय ने देश में अपरिचालित और अल्प परिचालित हवाईअड्डों से क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने और जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाने के लिए 21-10-2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)-उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) आरंभ की है। उड़ान, एक बाजार

आधारित योजना है। इच्छुक एयरलाइनें, विशेष मार्गों पर, मांग के अपने आकलन के आधार पर "उड़ान" योजना के तहत बोली प्रक्रिया के समय अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। ऐसा हवाईअड्डा/हवाई पट्टी/हेलीपोर्ट/ वाटर एयरोड्रम, जो क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)-उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) के अंतर्गत अवार्ड किए गए मार्गों में शामिल है और आरसीएस प्रचालन आरंभ करने के लिए उसके स्तरोन्नयन/विकास की आवश्यकता है, को "अपरिचालित और अल्प परिचालित हवाईअड्डों का पुनरुद्धार" योजना के तहत विकसित किया जाता है। "उड़ान" योजना के तहत अवार्ड किए गए हवाईअड्डों के पुनरुद्धार / उन्नयन के लिए भारत सरकार ने "अपरिचालित और अल्प परिचालित हवाईअड्डों का पुनरुद्धार" योजना के तहत 4500 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। अब तक, उड़ान योजना के तहत चार दौर की बोलियों के आधार पर, विभिन्न एयरलाइनों को 948 वैध मार्ग आवंटित किए गए हैं, जिनमें उन 31 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में, 14 वाटर एयरोड्रमों और 36 हैलीपैडों सहित, 154 आरसीएस हवाईअड्डों को जोड़ने वाले मार्ग शामिल हैं, जिनकी, देश में आरसीएस उड़ानों के प्रचालन के लिए पहचान की गई है। दिनांक 17-03-2022 की स्थिति के अनुसार, 66 हवाईअड्डों को जोड़ने वाले 409 आरसीएस मार्गों पर प्रचालन आरंभ किया गया है, जिनमें 2 वाटर एयरोड्रम और 8 हेलीपोर्ट शामिल हैं।

मेट्रो शहरों के हवाईअड्डों सहित, हवाईअड्डों का विस्तार और विकास एक सतत प्रक्रिया है, और इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) या संबंधित हवाईअड्डा प्रचालन द्वारा समय-समय पर वाणिज्यिक व्यवहार्यता, यातायात मांग, भूमि की उपलब्धता आदि के आधार पर किया जाता है। हवाईअड्डों के विस्तार और विकास के लिए भूमि की उपलब्धता के मुद्दों को संबंधित राज्य सरकारों सहित संबंधित स्टेकधारकों के साथ नियमित रूप से उठाया जाता है। मांग के आधार पर, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद हवाईअड्डों पर संबंधित हवाईअड्डा प्रचालकों ने विस्तार कार्य आरंभ किया है।

\*\*\*\*\*

क्र.सं.	हवाईअड्डे का नाम	राज्य
1	आसनसोल	पश्चिम बंगाल
2	आइजोल (ट्यूरियल)	मिजोरम
3	बेलूरघाट	पश्चिम बंगाल
4	चाकुलिया	झारखंड
5	झापारिज़ो	अरुणाचल प्रदेश
6	दीसा	गुजरात
7	देवघर	झारखंड
8	धालभूमगढ़	झारखंड
9	डोनाकोडा	आंध्रप्रदेश
10	जोगबनी	बिहार
11	कैलाशहर	त्रिपुरा
12	कमलपुर	त्रिपुरा
13	खंडवा	मध्य प्रदेश
14	खोवाई	त्रिपुरा
15	मालदा	पश्चिम बंगाल
16	मुजफ्फरपुर	बिहार
17	नादिरगुल	तेलंगाना
18	पन्ना	मध्य प्रदेश
19	रक्सौल	बिहार
20	सतना	मध्य प्रदेश
21	सेला	मेघालय
22	वेल्लोर	तमिलनाडु
23	वारंगल	तेलंगाना
24	तंजावुर (सीई)	तमिलनाडु

